

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1739/2007

- श्रीमती विजय रानी पत्नी स्वर्गीय श्री अजय कुमार, निवासी 5/288, सहयोग नगर, भरतपुर, जिला, भरतपुर।
- संजीव पुत्र स्वर्गीय श्री अजय कुमार, निवासी 5/288, सहयोग नगर, भरतपुर, जिला, भरतपुर।
- राजीव पुत्र स्वर्गीय श्री अजय कुमार, निवासी 5/288, सहयोग नगर, भरतपुर, जिला, भरतपुर।
- अमित पुत्र स्वर्गीय श्री अजय कुमार, निवासी 5/288, सहयोग नगर, भरतपुर, जिला, भरतपुर।
- पुनीत पुत्र स्वर्गीय श्री अजय कुमार, निवासी 5/288, सहयोग नगर, भरतपुर, जिला, भरतपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- श्याम बिहारी पुत्र श्री जगेश्वर दयाल, निवासी सहयोग नगर, भरतपुर।
- सुरेश चंद शर्मा पुत्र श्री लीलाधर शर्मा, निवासी सहयोग नगर, भरतपुर।

---प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एस.के. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्रीमती सुरभि अग्रवाल के साथ

प्रतिवादी की ओर से : श्री लक्ष्मण मीणा, पीपी
श्री रिनेश गुप्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

आदेश

06/03/2024

रिपोर्ट करने योग्य

1. इस आपराधिक विविध याचिका के माध्यम से धारा 482 सीआरपीसी के तहत, 13.06.2007 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 85/2006 में पारित आदेश और 14.10.2002 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, भरतपुर द्वारा श्याम बिहारी बनाम अजय कुमार शीर्षक वाले मामले संख्या 4/1997 में पारित आदेश को रद्द करने और गैर-याचिकाकर्ताओं संख्या 2 और 3 द्वारा धारा 133 सीआरपीसी के तहत दायर शिकायत को खारिज करने के लिए एक प्रार्थना की गई है।
2. दोनों पक्षों के वकीलों को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. ऐसा प्रतीत होता है कि गैर-याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (संक्षेप में "एडीएम") के समक्ष धारा 133 सीआरपीसी के तहत एक शिकायत दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने एक कमरा बनाकर और दो खंभे लगाकर एक गेट लगाकर 6-8 फीट चौड़ी एक सार्वजनिक गली को अवरुद्ध कर दिया है और इस तरह बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपद्रव पैदा किया है। शिकायत को कुछ पड़ोसियों यानी सुधा रानी, दौलत राम, कमल किशोर और लक्ष्मण, सभी सहयोग नगर, भरतपुर के निवासियों के हलफनामों द्वारा समर्थित किया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट ने 27.05.1997 को एक सशर्त आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को धारा 133 की उप-धारा 1 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक गली से पक्का निर्माण हटाने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ताओं पर सशर्त आदेश की तामील होने पर, उन्होंने शिकायत का जवाब दाखिल किया और दोनों पक्षों के घरों के बीच किसी भी सार्वजनिक गली के अस्तित्व से स्पष्ट रूप से इनकार किया। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि उन्होंने 17.07.1972 की पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से एक विजय रानी से सहयोग नगर, भरतपुर में स्थित मकान नंबर 05/288 की भूमि खरीदी और उनके घरों के पश्चिमी तरफ, 20 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध है, जिस पर उनके घरों का मुख्य द्वार

खुलता है। यह तर्क दिया गया कि वह निर्माण, जिसके बारे में गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक भूमि पर बनाए जाने का आरोप लगाया गया है, मूल रूप से उनकी अपनी भूमि पर स्थित है। गैर-याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे से और जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से उनके निर्माण को ध्वस्त कराने के इरादे से धारा 133 सीआरपीसी के तहत यह झूठी शिकायत दायर की है। फिर विद्वान जिला मजिस्ट्रेट ने एक जांच करने के लिए आगे बढ़े और साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिए, उसके बाद 14.10.2002 के अंतिम आदेश से, 27.05.1997 के सशर्त आदेश को निरपेक्ष बना दिया और याचिकाकर्ताओं को शिकायत के साथ संलग्न नक्शे में एबीसीडी के रूप में चिह्नित सार्वजनिक गली से 15 दिनों की अवधि के भीतर निर्माण हटाने का निर्देश दिया, हालांकि, निर्माण को पुलिस की सहायता से हटाया जाएगा।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करके 14.10.2002 के अंतिम आदेश को चुनौती दी और बताया कि यूआईटी, भरतपुर ने याचिकाकर्ताओं की खरीदी गई भूमि यानी मकान नं. 5/288, सहयोग नगर, भरतपुर को नियमित कर दिया है। यूआईटी, भरतपुर द्वारा जारी याचिकाकर्ताओं के भूखंड के पंजीकृत पट्टे में, विवादित गली को एक सार्वजनिक गली के रूप में नहीं दिखाया गया है। इसी तरह, आस-पास के भूखंडों के बिक्री विलेखों द्वारा सार्वजनिक गली का अस्तित्व साबित नहीं हुआ है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर की अदालत ने 13.06.2007 के आदेश से योग्यता के आधार पर पुनरीक्षण याचिका का फैसला करते हुए, अवलोकन किया कि यूआईटी, भरतपुर द्वारा याचिकाकर्ताओं के भूखंड के संबंध में जारी किए गए पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में, हालांकि, सार्वजनिक गली का अस्तित्व नहीं दिखाया गया है, लेकिन बिक्री विलेख में इसका उल्लेख है। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने उन गवाहों से प्रतिवाद नहीं किया, जिन्होंने गैर-याचिकाकर्ताओं के मामले के समर्थन में अपने हलफनामे दायर किए थे। पुनरीक्षण न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के बारे में भी उल्लेख किया, लेकिन अवलोकन किया कि यह मुकदमा विवादित गली के संबंध में नहीं है और अंत में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्माण हटाने के आदेश की पुष्टि की और 13.06.2007 के आदेश से पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, यह याचिका दायर की गई है।

5. दोनों चुनौती दिए गए आदेशों की योग्यता पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि तत्काल याचिका दायर करने पर, 29.05.2009 से विवादित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है, और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के निर्माण को हटाने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को निष्पादित नहीं किया गया है।

6. शुरुआत में, यह नोट किया जा सकता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 133 संहिता के अध्याय X के तहत परिकल्पित है जो "सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने" से संबंधित है। धारा 133 उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त आदेश के बारे में बात करती है, जिसके लिए एक जिला मजिस्ट्रेट या एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया है, को शक्तियां सौंपी गई हैं। संबंधित प्राधिकारी इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त होने पर और साक्ष्य के आधार पर, यदि कोई हो, जो मामले को धारा 133 की उप-धारा 1 के तहत सूचीबद्ध छह श्रेणियों में से किसी एक में लाने के लिए आमंत्रित करता है। प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर, प्राधिकारी सशर्त आदेश पारित कर सकता है, जिसे विरोधी पक्ष पर तामील किया जाना आवश्यक है और तामील होने के बाद, विरोधी पक्ष या व्यक्ति जिसे आदेश संबोधित किया गया है, वह आदेश का पालन कर सकता है [धारा 135(ए)] या यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे आदेश के खिलाफ कारण बताना होगा [धारा 135(बी)]। वर्तमान मामला धारा 135(बी) की श्रेणी में आता है जहां याचिकाकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और किसी भी सार्वजनिक गली के अस्तित्व से इनकार किया, साथ ही उनके निर्माण को सार्वजनिक गली पर एक बाधा होने से भी इनकार किया। ऐसी स्थिति में, धारा 137 सीआरपीसी के तहत कथित सार्वजनिक गली के संबंध में किसी भी सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व के बारे में प्रारंभिक जांच करना जिला मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक था। धारा 138 सीआरपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेने से पहले धारा 137 सीआरपीसी का प्रावधान अनिवार्य है। धारा 138 पार्टियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने से संबंधित है। धारा 139 और 140 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार, मजिस्ट्रेट धारा 137 या 138 सीआरपीसी के तहत एक जांच के उद्देश्य के लिए किसी भी विशेषज्ञ निकाय या व्यक्ति की सहायता लेने के लिए सशक्त है। धारा 142 एक

निषेधाज्ञा जारी करने का प्रावधान करती है, यदि एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 133 के तहत एक आदेश दे रहा है, यह विचार करते हुए कि जनता को एक गंभीर प्रकार के आसन्न खतरे या चोट को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। मजिस्ट्रेट धारा 143 सीआरपीसी के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक उपद्रव को दोहराने या संचालित न करने का आदेश पारित करने के लिए भी सशक्त है।

7. धारा 133 सीआरपीसी की पूरी योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव को रोकना है, मूल रूप से एक मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा त्वरित और तेज कार्रवाई करने के उद्देश्य से, जहां किसी भी सार्वजनिक उपद्रव या बाधा को बड़े पैमाने पर जनता के अधिकार के खिलाफ साबित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि संहिता की धारा 133 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने और इसके दायरे को लागू करने के लिए, संपत्ति या स्वास्थ्य के लिए एक आसन्न खतरा होना चाहिए और उसी से बड़े पैमाने पर जनता के लिए परिणामी उपद्रव होना चाहिए। वास्तव में, संहिता की धारा 133 का उद्देश्य अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उपद्रव को रोकना है और वह भी उस तीव्रता की आपातकालीन परिस्थितियों में कि यदि मजिस्ट्रेट तुरंत सहारा लेने में विफल रहता है, तो इसका परिणाम जनता को अपूरणीय क्षति होगा। इसलिए, यह माना जा सकता है कि धारा 133 सीआरपीसी के तहत परिकल्पित आदेश मूल रूप से बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए है और किसी व्यक्ति के किसी भी दीवानी और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पारित नहीं किया जा सकता है। कोई भी निजी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दीवानी या कानूनी अधिकारों के संबंध में कोई राहत प्राप्त करने के लिए धारा 133 सीआरपीसी के तहत परिकल्पित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों को लागू नहीं कर सकता है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वसंत मंगा निकुंवा बनाम बाबूराव भीकन्ना नायडू (मृतक) बाय एलआरएस. [(1995) Suppl. 4 SCC 54] के मामलों में अवलोकन और निर्णय दिया है कि धारा 133 सीआरपीसी के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जहां बाधा या उपद्रव लंबे समय से अस्तित्व में है और उस स्थिति में, पीड़ित पक्ष के लिए एकमात्र उपाय शिकायतों के निवारण के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष संपर्क करना था। धारा 133 केवल आपातकाल और समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए

तत्काल खतरे के मामले में आकर्षित होती है। निर्णय के प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार पुनरुत्पादित हैं: -

“धारा 133 का एक पठन स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की एक रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त होने पर और ऐसे साक्ष्य लेने पर सशक्त किया गया है जैसा कि वह मानता है कि कोई भी इमारत, तम्बू या संरचना ऐसी स्थिति में है कि, हटाने, मरम्मत, या समर्थन के बिना गिरने की संभावना है और इस तरह पड़ोस में रहने या व्यवसाय करने वाले या गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट पहुंचा सकती है और इसके परिणामस्वरूप वह ऐसी इमारत, तम्बू या संरचना या पेड़ को हटाने, मरम्मत करने या समर्थन प्रदान करने के लिए समय निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के लिए यह विचार करने पर दो विकल्प खुले हैं कि क्या संरचना, भवन आदि ऐसी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है जिसे पड़ोस या राहगीरों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरे को टालने के लिए तुरंत ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जब तक कि उन्हें सार्वजनिक खतरे को टालने के लिए उपयुक्त रूप से मरम्मत या समर्थन नहीं दिया जा सकता है या इसे हटा दिया जा सकता है, आदि। धारा 133 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की पूर्व शर्त संपत्ति के लिए आसन्न खतरा और जनता के लिए परिणामी उपद्रव है। इमारत को हटाने की इतनी तत्काल आवश्यकता है क्योंकि इसके गिरने की संभावना है और पड़ोस में रहने या व्यवसाय करने वाले या राहगीरों को चोट पहुंचा सकती है। उपद्रव एक साथ होने वाला कार्य है जिसके परिणामस्वरूप संभावित पतन आदि के कारण जीवन या संपत्ति को खतरा होता है। इमारत की खतरनाक स्थिति वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। धारा पड़ोस में रहने या व्यवसाय करने वाले या राहगीरों को होने वाली चोटों तक सीमित है। प्रत्येक मामले को प्रत्येक मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में माना जाना चाहिए।

5. टी.के.एस.एम. कल्याणसुंदरम बनाम कल्याणी अम्मल [(1975) 2 MLJ 93 (Mad)] में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि कथित उपद्रव लंबे समय से अस्तित्व में होगा। उस मामले में परिस्थितियां और साक्ष्य यह साबित नहीं करते थे कि धारा 133 के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता मौजूद थी। इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जहां बाधा या उपद्रव लंबे समय से अस्तित्व में है और पीड़ित पक्ष के लिए एकमात्र उपाय सिविल कोर्ट में जाना था। यह भी माना गया कि धारा 133 केवल आपातकाल और समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए तत्काल खतरे के मामलों में आकर्षित होती है। तदनुसार उस मामले में तथ्यों पर, यह माना गया कि उस मामले में offending संरचना को हटाने के लिए कोई तत्काल खतरा या आपातकाल नहीं था। यह भी स्थापित कानून है कि धारा 133 का सहारा दीवानी कार्यवाही का विकल्प नहीं हो सकता है और पार्टियों को उपलब्ध दीवानी उपाय का सहारा लेना चाहिए और संहिता की धारा 133 के प्रावधानों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

9. वसंत मंगा मिकुंबा (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात डिसिडेंडी की पुष्टि और पालन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एमपी बनाम केडिया लेदर एंड लिंकर [(2003) 7 SCC 389]** के मामले में फिर से किया गया, जिसमें यह माना गया था कि धारा 133 सीआरपीसी के आवेदन को लाने के लिए, संपत्ति के लिए एक आसन्न खतरा और जनता के लिए परिणामी उपद्रव होना चाहिए। संहिता की धारा 133 का प्रावधान सामान्य जनता को कठिनाई पैदा करने वाले अपवाह और वायु निर्वहन के कारण सार्वजनिक उपद्रव को दूर करने के लिए सहायता में लिया जा सकता है। यह अवलोकन किया गया कि संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही दीवानी कार्यवाही की प्रकृति में है न कि आपराधिक कार्यवाही की, जिसे मजिस्ट्रेट की धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है।

10. हाथ में लिए गए मामले पर आते हुए और अंतर्निहित उद्देश्य के आधार पर तथ्यों पर विचार करते हुए, जहां धारा 133 सीआरपीसी के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को लागू किया जा सकता है, यह गैर-याचिकाकर्ताओं का स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कमरे और दो खंभों का पक्का निर्माण किया गया है और कथित सार्वजनिक गली को अवरुद्ध करने के लिए गेट लगाया गया है। गैर-याचिकाकर्ताओं ने अवधि, दिनांक, माह या वर्ष का खुलासा नहीं किया है कि कथित निर्माण याचिकाकर्ताओं द्वारा कब किया गया था। इसके अलावा, गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी सार्वजनिक गली के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और वह भी ऐसी कोई सार्वजनिक गली बड़े पैमाने पर जनता द्वारा उपयोग के लिए साइट पर उपलब्ध थी। 14.10.2002 के मजिस्ट्रेट के चुनौती दिए गए आदेश में, केवल चार व्यक्तियों यानी सुधा रानी, दौलत राम, कलाम किशोर और एक लक्ष्मण द्वारा हलफनामे दायर करने का उल्लेख है, जो सभी केवल सहयोग नगर, भरतपुर के निवासी हैं। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से किसी भी सार्वजनिक गली के अस्तित्व से इनकार किया है और वह भी बड़े पैमाने पर जनता द्वारा उपयोग नहीं किया जाना है। मजिस्ट्रेट का चुनौती दिया गया आदेश यह नहीं दर्शाता है कि सार्वजनिक गली के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने के लिए और ऐसी सार्वजनिक गली पर याचिकाकर्ताओं के निर्माण द्वारा बड़े पैमाने पर

जनता के लिए किसी भी आसन्न खतरे के बारे में क्या साक्ष्य या अन्य सामग्री उनके सामने रिकॉर्ड पर आई थी। यहां तक कि आदेश भी यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए मौन है कि धारा 137 सीआरपीसी के तहत एक जांच आयोजित करने के लिए कि कथित गली, यदि अस्तित्व में थी, एक सार्वजनिक गली है या नहीं, और क्या इसका उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किया जा रहा था। जब याचिकाकर्ताओं ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 133(1) के तहत पारित सशर्त आदेश का जवाब दिया और शिकायत का जवाब दाखिल किया, साथ ही यूआईटी, भरतपुर द्वारा जारी उनके पंजीकृत पट्टे सहित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिसमें साइट पर कथित सार्वजनिक गली का गैर-अस्तित्व दिखाया गया था, तो मजिस्ट्रेट के लिए पहले बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए एक सार्वजनिक गली के अस्तित्व के बारे में एक जांच करना आवश्यक और अनिवार्य था, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के निर्माण को हटाने के लिए अंतिम आदेश पारित करने के लिए केवल इस आधार पर आगे बढ़े कि याचिकाकर्ताओं ने गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में प्रस्तुत किए गए चार व्यक्तियों के हलफनामों के निष्पादकों से प्रतिवाद नहीं किया। तीन-चार व्यक्ति disinterested गवाह नहीं हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों के लिए किसी भी आसन्न खतरे के निष्कर्ष को दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए, यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 14.10.2002 को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित चुनौती दिया गया आदेश धारा 133 सीआरपीसी के दायरे और दायरे के भीतर नहीं है और धारा 133 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करने के लिए आवश्यक कानून के जनादेश के खिलाफ पारित किया गया है।

11. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर की अदालत ने 14.10.2002 के चुनौती दिए गए आदेश के खिलाफ अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 133 सीआरपीसी के दायरे में एक आदेश पारित करने के लिए कानून के तहत आवश्यक आवश्यक सामग्री को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक सिविल कोर्ट की तरह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पार्टियों के दस्तावेजों का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ी। वर्तमान मामले में, जब दो समूहों की निजी पार्टियों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या 6-8 फीट चौड़ी विवादित गली एक सार्वजनिक रास्ता है या एक निजी भूमि है, तो यह स्पष्ट रूप से एक विवादित तथ्य का प्रश्न है जिसे पुनरीक्षण

न्यायालय द्वारा संबोधित नहीं किया जाना चाहिए था, मजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए, खासकर जब पुनरीक्षण न्यायालय को यह ध्यान में लाया गया है कि पार्टियों के बीच एक दीवानी मुकदमा लंबित है जैसा कि आदेश में ही नोट किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 133 सीआरपीसी के तहत गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर शिकायत का जवाब दाखिल करने के बाद, ऐसे प्रश्न का उत्तर केवल सामग्री साक्ष्य का मूल्यांकन और जांच करने के बाद दिया जा सकता था, जिसके लिए दोनों पक्षों को अवसर दिया जाना आवश्यक था। इसलिए पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे यात्रा की। इससे भी कम से कम, ऐसी विवादित तथ्य का प्रश्न, अचल संपत्ति से संबंधित, धारा 133 सीआरपीसी के तहत सारांश कार्यवाही में निर्णय नहीं किया जा सकता था। आपराधिक पुनरीक्षण में अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कम से कम पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं। इसलिए, यह अदालत इस विचार से है कि 13.06.2007 का चुनौती दिया गया आदेश भी स्पष्ट और गंभीर अवैधता से ग्रस्त है और अधिकार क्षेत्र की त्रुटि के कारण भी मूल्यवान है और न्याय की विफलता की ओर ले जाता है।

12. कुछ इसी तरह के तथ्यों और परिस्थितियों में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने काशेतर पाल सिंह उर्फ कृपाल सिंह बनाम हरपाल सिंह [2016 0 सुप्रीम (एचपी) 2371] सीआर.एमएमओ नंबर 109 ऑफ 2014 दिनांक 28.12.2016 को तय किया गया, ने निजी पार्टियों के बीच विवाद का निर्णय करने से इनकार कर दिया, जो सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित नहीं था और बड़े पैमाने पर जनता के सामान्य हित का नहीं था, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के दायरे में और अदालत ने निम्नानुसार माना: -

“सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्यवाही का इरादा जनता के दो सदस्यों के बीच निजी विवाद को निपटाना नहीं है। यह स्थापित कानून है कि यदि कोई विवाद दीवानी प्रकृति का है तो धारा 133 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा विवाद का विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त धारा के प्रावधानों का उपयोग केवल बड़े पैमाने पर जनता के सामान्य हित में एक सार्वजनिक अधिकार के संबंध में विवाद को निपटाने के लिए किया जा सकता है।”

13. यह न्यायालय इस विचार से है कि हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर, याचिकाकर्ताओं और गैर-याचिकाकर्ताओं के घरों के बीच कथित रूप से 6-8 फीट चौड़ी एक गली पर अतिक्रमण के बारे में विवाद, वस्तुतः जनता के दो सदस्यों के बीच एक निजी विवाद है और ऐसे निजी विवाद को निपटाने के लिए सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्यवाही को लागू नहीं किया जा सकता था। यह एक अतिरिक्त बिंदु है कि यह भीL. प्रश्न योग्य है कि ऐसी गली एक सार्वजनिक गली थी या नहीं, वह भी बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए? वर्तमान मामले के तथ्यों में, ऐसे विवाद का न तो निर्णय किया गया है और न ही धारा 133 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में इसका फैसला किया जा सकता है। इस प्रकार, गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर शिकायत को धारा 133 सीआरपीसी के दायरे में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था और ऐसी शिकायत पर पारित चुनौती दिए गए आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण, अवैध हैं क्योंकि बिना अधिकार क्षेत्र के हैं। इसलिए, अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय के लिए अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों चुनौती दिए गए आदेशों को रद्द करना वांछनीय है।

14. यहां ऊपर किए गए चर्चा का परिणाम यह है कि यह याचिका स्वीकार की जाती है। 14.10.2002 और 13.06.2007 के चुनौती दिए गए आदेशों को एतद्वारा रद्द किया जाता है और धारा 133 सीआरपीसी के तहत गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर शिकायत खारिज की जाती है। पक्षकार अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

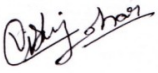
15. हालांकि, गैर-याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए कोई भी अन्य कानूनी कार्रवाई करें, जैसा कि सलाह दी जा सकती है, यदि कोई हो।

16. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), जे

नितिन/432

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़